रविशंकर प्रसाद
RAVI SHANKAR PRASAD

मंत्री
संचार, विधि एवं न्याय
एवं
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी
भारत सरकार
MINISTER OF
Communications, Law & Justice
and
Electronics and Information Technology
Government of India

D.O. No. 20-03/2019-PR

24 OCT 2019

Dear Shri Sarbananda Sonowal Ji,

I am enclosing a letter from Secretary, Department of Telecommunications, Government of India addressed to the Chief Secretary requesting for intervention by the State Government in the matter of payment of electricity dues by Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL), a Public Sector Undertaking, providing telecommunications services.

You will appreciate that BSNL maintains a vast network, even in remote areas. In fact, BSNL is operating 23,000 rural wirelines exchanges across the country. Disconnection of electricity connection due to non-payment for electricity supplied to Mobile phone towers, wireline telephone exchanges and administrative buildings of BSNL is causing disruption of services including in rural, hilly and inaccessible areas where BSNL may, perhaps, be the only source of telecommunications for local residents.

It is requested that the State Government favourably considers the request for moratorium on payment by BSNL to State Electricity Board/Discoms till 31.03.2020 and thereafter BSNL can settle the dues in 4 quarterly instalments with waiver of interest/penalty/surcharge.

Further, payments due to BSNL from State Government Departments/Undertakings may kindly be settled on priority.

I look forward to a favourable response from the State Government.

With regards,

Yours sincerely,

(RAVI SHANKAR PRASAD)

Shri Sarbananda Sonowal
Chief Minister of Assam,
CM Block, Janata Bhawan,
Dispur,
Assam – 781006

ISSUED

Sanchar Bhawan, 20 Ashoka Road, New Delhi - 110 001
Phone : 011-23739191, 23372177 Fax : 011- 23372428

रविशंकर प्रसाद
RAVI SHANKAR PRASAD

सत्यमेव जयते

दिनांक: अक्तूबर, 2019
मंत्री
संचार, विधि एवं न्याय
एवं
इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी
भारत सरकार
MINISTER OF
Communications, Law & Justice
and
Electronics and Information Technology
Government of India

प्रिय श्री रघुबर दास जी,

24 OCT 2019

मैं, सचिव, दूरसंचार विभाग, भारत सरकार के मुख्य सचिव को सम्बोधित पत्र को संलग्न कर रहा हूँ जिसमें भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो दूरसंचार सेवाएं प्रदान कर रहा है, के बिजली बिल की बकाया राशि के भुगतान के मामले में राज्य सरकार की ओर से उपाय करने का अनुरोध किया गया है।

2. आप इस बात की सराहना करेंगे कि बीएसएनएल ने दूरस्थ क्षेत्रों में भी व्यापक नेटवर्क बनाया हुआ है। वस्तुत: देश भर में बीएसएनएल के 23,000 ग्रामीण वायरलाइन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं। बीएसएनएल के मोबाइल फोन टावरों, वायरलाइन टेलीफोन एक्सचेंजों और प्रशासनिक भवनों में प्रदान की गई बिजली का भुगतान न करने के कारण बिजली के कनेक्शनों के कटने से ग्रामीण, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों जहां संभवत: बीएसएनएल, स्थानीय निवासियों के लिए दूरसंचार का एकमात्र साधन है, सहित अन्य क्षेत्रों में भी सेवाओं में बाधा उत्पन्न हो रही है।

3. यह अनुरोध है कि राज्य सरकार दिनांक 31.03.2020 तक बीएसएनएल द्वारा राज्य बिजली बोर्ड/डिस्कॉम को भुगतान के स्थगन हेतु किए गए अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे और उसके पश्चात बीएसएनएल ब्याज/दण्ड/अधिप्रभार की छूट के साथ 4 त्रैमासिक किश्तों में बकाया राशि का निपटान कर सकता है।

4. इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार के विभागों/उपक्रमों के बीएसएनएल पर बकाया भुगतान को कृपया प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए।

मैं राज्य सरकार से अनुकूल प्रत्युत्तर की आशा करता हूँ।

सादर,

भवदीय,

(रविशंकर प्रसाद)

श्री रघुबर दास,
मुख्यमंत्री,
झारखण्ड सरकार,
मुख्यमंत्री हाऊस,
पहली मंजिल, प्रोजेक्ट बडिंग,
सीएमओ, रांची, झारखण्ड-834001.

जारी किया